आयातित गेहूं, चावल तथा माइलों में भण्डारण तथा वितरण पर व्यय

998. **श्री बृज भूषण तिवारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान कुल कितने मूल्य के (लागत तथा भाड़ा) गेहूं, चावल तथा माइलों का आयात किया गया तथा उसके भण्डारण और वितरण पर कितना खर्च आया ; और

(ख) प्रति क्विंटल उसका औसत मूल्य कितना पड़ा तथा वह उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर बेचा गया ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1975-76 के दौरान आयात किए गए गेहूं, चावल और माइलों का कुल मूल्य (लागत तथा भाड़ा) 1069.13 करोड़ रुपए था आयातित अनाजों के भण्डारण तथा वितरण पर हुए खर्च का ब्यौरा ठीक ठीक देना सम्भव नहीं है क्योंकि ये खर्चे देशी स्टाक पर हुए खर्च में मिला दिए जाते हैं ।

(ख) आयातित गेहूं, चावल और माइलों का औसत लागत मूल्य इस प्रकार है :—

	रु० प्रति क्विंटल
गेहूं आयातित	171.03
चावल आयातित सभी किस्में	242.61
माइलों आयातित	146.20

राज्य सरकारों को ये खाद्यान्न केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर, गेहूं के लिए 125/- रुपए प्रति क्विंटल चावल की विभिन्न किस्मों के लिए 135/- रुपए से 172 रुपए प्रति क्विंटल और 7-11-76 तक माइलों के लिए 36/- रुपए प्रति क्विंटल और 8-11-76 से 70/- रुपए प्रति क्विंटल दिए गए थे । राज्य सरकारें खाद्यान्नों के उपभोक्ताओं को बेचने से पूर्व इन निर्गम मूल्यों में अपनी वितरण संबंधी खर्च जोड़ती हैं ।

Abolition of State Farms

999. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to a Statement made by the Union Home Minister saying that the State Farms like Suratgarh should be distributed to small peasants and wanting to do away with State Farms and cooperative farms with mechanisation;

(b) if so, gist of the statement and the reaction of the Government; and

(c) whether this is likely to affect the existing State farms and the working of the Public Undertaking like the State Farms Corporation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). The reference presumably is to the remarks of the Union Home Minister in the Seminar on "Planning and Implementation Systems" at the Indian Institute of Public Administration, New Delhi on the 25th April, 1977. As the Union Home Minister had clarified in the beginning of his speech, his remarks were made in his personal capacity and not as the Union Home Minister.

(c) In view of (a) and (b) above, question does not arise.